Knowledgeable Research (KR)
ISSN: 2583-6633 | CODEN: KRABAU
International Open-Access Peer-Reviewed Refereed Multidisciplinary Journal
https://knowledgeableresearch.com
Vol. 5, Issue 05, May,2026

Received: 09/04/2026 | Accepted: 21/05/2026 | Published: 30/05/2026

भारतीय कृषि व ग्रामीण विकास में योजनायें: चुनौतियां और समाधान

प्रो0 (डा0) सत्येंद्र नारायण *
प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत

सारांश-

जब हम गांव शब्द को परिभाषित करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसे क्षेत्र का परिदृष्य उभरकर आता है, जहां पर जीवन की मूलभूत सुविधाओं जैसे- सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का प्रायः अभाव पाया जाता है। मूलभूतः सुविधाओं के अभाव के साथ-साथ गांवो में गरीबी, बेकारी तथा बेरोजगारी एक जटिल समस्या है जोकि गांवों के विकास में सबसे बड़ी बाधा के रूप में उभरकर सामने आ रही है। विश्व में ऐसे बहुत कम देश हैं जिनकी 74 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती हो। इस प्रकार ग्रामीण ही उस देश की सम्पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के आधार है। जब तक गांवो में रहने वाली 70 प्रतिशत से अधिक आबादी का विकास नहीं होगा, तब तक भारत का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। राष्ट्र के समग्र और सतत् विकास के लिए ग्रामीण विकास केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य शर्त है। ग्रामीण विकास का अर्थ केवल कृषि विकास से ही नहीं है अपितु ग्रामीणों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है। इसमें बुनियादी ढांचा, जैसे- सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवायें, शिक्षा, डिजीटल साक्षरता और आर्थिक स्वावलम्बन जैसे व्यापक आयाम सम्मिलित हैं। भारत देश में वर्तमान सरकार भी कृषि विकास के प्रति गम्भीर लग रही है। यह शोध पत्र ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने तथा ग्रामीण विकास में विभिन्न सरकारी योजनाऐं, उनके प्रभाव, क्रियान्वयन, चुनौती व उनके समाधान पर आधारित है।

सांकेतिक शब्द - *ग्रामीण विकास, कृषि विकास, पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग।*

***Corresponding Author:**
प्रो0 (डा0) सत्येंद्र नारायण
Email: satendranarayan5505@gmail.com

प्रस्तावना –

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि "भारत का भविष्य उसके गांवों में निहित है।" अर्थात् जब तक भारत के गांवों का चहुंमुखी विकास नहीं होगा, तब तक भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता है। भारतीय कृषि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह श्रम प्रधान व कृषि श्रम पर आधारित है। यह सच है कि इस भारतीय कृषि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारतीय कृषक व्यापारी नहीं, वह तो एक तपस्वी है जो दिन भर तपता रहता है तथा स्वेदित रहता है। आज भी भारत में कृषि की प्रधानता का स्वरूप कायम है और भारत की पहचान एक कृषि प्रधान देश के रूप में बनी हुई है। गांवो में बसने वाली आबादी की जीविका का मुख्य साधन कृषि, पशुधन और कृषि से जुड़े हुए ही अन्य व्यवसाय है। कृषि के विकास पर ही औद्योगिक विकास व अन्य सभी

Copyright: © The authors. This article is open access and licensed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

क्षेत्रों का विकास टिका रहता है। अतः ग्रामीण विकास का अर्थ कृषक के विकास से लिया जाता है। सरकार गामीण विकास के लिए अनेक योजनायें व कार्यक्रम चलाती रहती हैं, जिनकी सफलता एवं असफलता तथा क्रियान्वयन की बाधाओं आदि के कारण कभी–कभी किसानों को अपने हक का इन्तजार करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अनेक ग्रामीण कृषकों को सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी सही समय पर न हो पाने के कारण भारतीय समाज में ग्रामीण विकास अभी बहुत अधिक नहीं हो सका, परन्तु विकास की ओर सतत अग्रसर है।

आजादी के बाद सामुदायिक ग्रामीण विकास को वरीयता देते हुए सर्वप्रथम सन् 1952 में सामुदायिक विकास योजनाओं के कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया जिसे काफी महत्व भी दिया गया। इसका शुभारम्भ प्रथम राष्ट्रपति स्व. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने किया था। इस कार्यक्रम का ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया था कि इसमें गामीणों की भागीदारी हो और उन्हें यह अपना कार्यक्रम प्रतीत हो। राष्ट्रीय ग्रामीण योजनाओं के तहत राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई और इसके लिए केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत प्रसार निदेशालय की स्थापना की गयी। प्रसार निदेशालय ने अपने माध्यमों से कृषि के नये सुधारों और उपयोगी जानकारियों को ग्रामीण कृषकों तक पहुंचाना आरंभ किया और साथ ही ग्राम सेवकों से लेकर राज्य स्तर के अधिकारियों तक के लिए कार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किये। किसानों के लिए उन्नत कृषि तकनीकी कार्यक्रम व उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इन सभी कार्यक्रमों से कृषि जगत में एक नई चेतना अच्छे प्रभाव के रूप में प्रभावित हुई। सामुदायिक ग्रामीण विकास (Community Rural Development) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास करना, गरीबी कम करना और आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। भारत में 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP) के माध्यम से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे में सुधार कर ग्रामीण जीवन स्तर को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

सामुदायिक ग्रामीण विकास के मुख्य घटक –

- सहभागी दृष्टिकोण – ग्रामीण लोगों की सक्रिय भागीदारी से योजना और कार्यान्वयन।
- सर्वांगीण विकास– कृषि, पशुपालन, सिंचाई, शिक्षा, और ग्रामीण उद्योगों का विकास।
- आत्मनिर्भरता– स्थानीय संसाधनों और कौशल का उपयोग करके आजीविका को बेहतर बनाना।
- बुनियादी ढांचा– सड़क, बिजली, और संचार व्यवस्था में सुधार।

मुख्य उद्देश्य –

- आत्मनिर्भरता– समुदाय में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाना और लोगों को

Copyright: © The authors. This article is open access and licensed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजने के लिए प्रेरित करना।

- गरीबी उन्मूलन– ग्रामीण युवाओं के लिए आजीविका और रोजगार के अवसर पैदा करना।
- जीवन स्तर में सुधार– स्वास्थ्य, स्वच्छता और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।
- शहरी–ग्रामीण अंतर कम करना– ग्रामीण क्षेत्रों को भी विकास का समान अवसर प्रदान करना।

क्रियान्वयन और चुनौतियां –

- सरकारी पहल– Ministry of Rural Development के माध्यम से कई योजनाओं को लागू किया जाता है।
- चुनौतियां– कमजोर निगरानी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, और स्थानीय स्वामित्व का अभाव।
- केंद्र सरकार की भूमिका– 1952 में शुरू की गई CDP योजना की सिफारिश 1952 Grow More Food Enquiry Committee ने की थी।

यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास के लिए एक शुरू की गई एक व्यापक रणनीति थी जो अभी भी ग्रामीण विकास का मुख्य आधार है।

आजादी के बाद भारत की उन्नति व प्रगति के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को आरंभ किया गया। कृषि विकास को ध्यान में रखते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–1956) में कृषि को वरीयता में प्रथम स्थान पर रखा गया। कृषि क्षेत्र के उन्नयन के लिए इसमें जो व्यापक प्रावधान किये गये उनके अच्छे परिणाम सामने आये । द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–1961) में कृषि को अनदेखा न करते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए औद्योगिक क्षेत्र में विकास को प्रधानता दी गई। इसी प्रकार तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–1966) में कृषि को वरीयता देते हुए कृषि का लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किया गया कि हम खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। इसके बाद भी अन्य पंचवर्षीय योजनाओं चतुर्थ (1969–1974), पंचम (1974–1978) का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता था। यह योजना रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन व रक्षा पर आधारित थी। षष्ठम योजना (1980–1985) एक अत्यन्त सफल योजना थी इसका उद्देश्य भी गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन व तकनीकी आत्मनिर्भरता था जो विशेष रूप से कृषि व ग्रामीणों के हितों से संबंधित था। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–1990) में खाद्यान्नों के उत्पादन पर ध्यान दिया गया। आठवी पंचवर्षीय योजना में (1992–1997) में कृषि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उत्पादन व उत्पादकता में सुधार का प्रयास हुआ। नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर आरंभ हुई। इसमें ग्रामीण विकास को केंद्रित किया गया। दसवी पंचवर्षीय योजना (2002–2007) यद्यपि मुख्य रूप से कृषि विकास पर आधारित नहीं थी परतु फिर भी कृषि तकनीकी व कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या बढ़ाने

Copyright: © The authors. This article is open access and licensed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

पर ध्यान दिया गया। इसके उपरान्त ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (2007–2012) डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी के समय में क्रियान्वयन हुई जिसका मुख्य विषय "तीव्र और अधिक समावेशी विकास" था। अन्तिम पंचवर्षीय योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) में ग्रामीण परिवर्तन को एक प्रमुख रणनीतिक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, जिसका उद्देश्य कृषि व उससे संबंधित क्षेत्रों में स्थायी विकास को सुनिश्चित करना था। इस योजना का मुख्य फोकस "तेज, अधिक समावेशी और सतत् विकास" था, जिसमें कृषि क्षेत्र व ग्रामीण विकास के लिए आय के साधन बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारत में अब पंचवर्षीय योजनायें नहीं चल रही हैं। 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर "नीति आयोग" का गठन किया गया, जो अब तीन साल का एक्शन एजेंडा और दीर्घकालिक नीतियाँ तैयार करता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में सभी सरकारों ने अपनी योजनाओं में कृषि व ग्रामीण विकास को सर्वोपरि रखा और जिसका सतत् विकास भारत को उन्नति प्रदान कर रहा है।

ग्रामीण विकास में पंचायतीराज –

ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाएं (PRIs) आधारभूत ढांचा तैयार करने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और स्थानीय लोगों की भागीदारी (ग्राम सभा के माध्यम से) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये संस्थाएं ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के जरिए सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करती हैं और आत्मनिर्भर गांवों का निर्माण करती हैं।

पंचायती राज की मुख्य भूमिकाएं और कार्य–

- स्थानीय योजना और कार्यान्वयन– ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायतें स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास योजनाएं बनाती हैं और मनरेगा (MGNREGA) जैसी योजनाओं का संचालन करती हैं।
- आधारभूत ढांचा विकास– गाँवों में सड़क, सार्वजनिक शौचालय, जल निकासी, तालाब, और हाट–बाजार का विकास करना।
- सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण– यह सुनिश्चित करना कि ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों (SC/ST) और महिलाओं को विकास प्रक्रियाओं में निर्णय लेने का अवसर मिले,।
- सेवा वितरणरू शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, और कृषि संबंधी इनपुट (बीज, उर्वरक) का वितरण सुनिश्चित करना।

प्रमुख संस्थान और पोर्टल–

- पंचायती राज मंत्रालय (भारत सरकार)– यह राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन की देखरेख करता है।
- इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (राजस्थान)– पीआरआई और ग्रामीण विकास में मानव संसाधन

Copyright: © The authors. This article is open access and licensed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

विकसित करने वाला एक प्रमुख संस्थान है।

- Rawat Books– पंचायती राज प्रणाली की कार्यप्रणाली और ग्रामीण विकास पर विशेष प्रकाश डालते हैं।
- ICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)– कृषि विकास के लिए पंचायतों के साथ मिलकर काम करता है।

ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका (IJASS) इस बात पर जोर देती है कि, पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, सार्वजनिक शौचालय, जल निकासी, तालाब, और हाट–बाजार के विकास के कार्यों में तेजी लाती हैं, जो एक आत्मनिर्भर ग्राम विकास के लिए अनिवार्य हैं।

पंचायती राज संस्थाएं (PRIs) ग्रामीण विकास में एक सुदृढ़ ग्रामीण भारत का निर्माण करने में अहम हैं।

ग्रामीण विकास में नई योजनाओं का समावेश –

भारत में ग्रामीण विकास और ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कई प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें मनरेगा (डळछत्म्ळ।) सबसे प्रमुख है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं –

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)

- उद्देश्य– ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी वाले रोजगार की सुरक्षा प्रदान करना।
- विशेषता– यह अकुशल शारीरिक श्रम (unskilled manual work) पर केंद्रित है।
- मुख्य कार्य– जल संरक्षण, वनीकरण, ग्रामीण संपर्क, बाढ़ नियंत्रण और सूखा–प्रवण क्षेत्रों में परिसंपत्ति निर्माण।

2.प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY&G)

- उद्देश्य– ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर या कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर प्रदान करना।
- सहायता– समतल क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये की सहायता।

3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

- उद्देश्य– गांव की सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ना ताकि हर मौसम में संपर्क बना रहे।

4. दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY&NRLM)

- उद्देश्य– गरीब ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित करना और उनके माध्यम से स्थायी आजीविका और कौशल विकास को बढ़ावा देना।

Copyright: © The authors. This article is open access and licensed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

5. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU&GKY)

- उद्देश्य– ग्रामीण युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।

6. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (SPMRM)

- उद्देश्य– ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करना, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर कम किया जा सके।

7. स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (SBM&G)

- उद्देश्य– ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुनिश्चित करना और खुले में शौच मुक्त (ODF) भारत का लक्ष्य प्राप्त करना।

8. पी.एम.– जनमन (PM-JANMAN)

- उद्देश्य– विशेष रूप से कमजोर जनजातिय समूहों के लिए सामाजिक–आर्थिक उत्थान योजना।

9. लखपती दीदी योजना

- उद्देश्य– स्वयंसहायता समूहों की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर वार्षिक आय बढ़ाने पर जोर।

10. जल–जीवन मिशन

- उद्देश्य– हर घर में नल से शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

11. विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)

- 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाला नया मिशन, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर और आजीविका को बढ़ावा देना है।

अन्य प्रमुख योजनाएं–

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
- सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY)
- संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)

चुनौतियां –

सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न प्रकार की बाधाऐं आती हैं, जो निम्न प्रकार हैं–

- जागरूकता का अभाव– ग्रामीणों को अपने अधिकारों और नई योजनाओं की पूरी जानकारी न होना।
- भ्रष्टाचार और बिचौलिये– धन का सही लाभार्थियों तक न पहुंच पाना।
- भौगोलिक बाधाएं– दुर्गम क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में कठिनाई।
- प्रशिक्षण की कमी– कौशल विकास (Skill Development) कार्यक्रमों का धरातल पर कमजोर होना।
- तकनीकी समस्या– ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और नेटवर्क की अस्थिरता।

Copyright: © The authors. This article is open access and licensed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

समाधान के सुझाव –

ग्रामीण विकास की गति तेज करने के लिए शोध पत्र निम्नलिखित सुझाव देता है –

- पारदर्शिता– 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) का अधिक प्रभावी उपयोग ताकि भ्रष्टाचार कम हो।
- सामुदायिक भागीदारी– ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त बनाना और सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) को अनिवार्य करना।
- सूचना का प्रसार– स्थानीय भाषाओं और रेडियोध्मोबाइल के माध्यम से योजनाओं का प्रचार–प्रसार।
- स्थानीय संसाधनों का उपयोग– सौर ऊर्जा और जैविक खेती (Organic Farming) जैसे स्थानीय समाधानों को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष –

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भारतीय कृषि व ग्रामीण विकास का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बनाये गये कार्यक्रम एवं नीतियों में कमी नहीं है लेकिन उनका क्रियान्वयन सफलतापूर्वक होना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक कृषक व ग्रामीण को खुद जागरुक होकर योजनाओं को समझकर अपने अधिकार को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा और अपनी पूर्ण इच्छाशक्ति एवं कर्मनिष्ठा के साथ अपने कार्यों को संपादित करना होगा, तब ही ग्रामीण विकास में तेजी आयेगी। वर्तमान समय में सरकार द्वारा खाद, बीज व एल.पी.जी. की सब्सिडी का सीधे ग्रामीणों के खातों में पहुंचाना एक महत्वपूर्ण व सराहनीय प्रयास है जिससे विकास के पथ पर अग्रसर होकर एक आदर्श राज्य, देश एवं लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे व सामाजिक खुशहाली की स्थिति बन सकेगी। उपरोक्त अध्ययन ग्रामीण विकास की योजनाऐं, ग्रामीण विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को पहचानने व उनके व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करने की एक दिशा हेतु प्रयास है।

सन्दर्भः

1. ग्रामीण विकास एवं नियोजन : रेखा शर्मा
2. प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास : ओमप्रकाश
3. कम्यूनिटी डेवलेपमेन्ट प्रोगाम इन इंडिया : किताब महल, इलाहावाद
4. भारत में ग्रामीण विकास : एस. आर. माहेश्वरी
5. दि चैलेन्जिंग विलेज कम्यूनिटी : जे. एम. हालपर्न
6. भारत में कृषि विकास : पी.सी जैन
7. इण्टरनेट व दैनिक समाचार–पत्र।

Copyright: © The authors. This article is open access and licensed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)